RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 167 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

छोटे वाहने से टोल लिया गया तो बूथों में आग लगाने की धमकी !

राज ठाकरे की राज्य सरकार को चेतावनी

मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने से रोका गया कि छोटे वाहनों को टोल शुल्क से छूट दी गई तो वे राज्य में टोल बूथों पर आग लगा देंगे। ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि टोल बूथ राज्य में नेताओं की आजीविका का साधन हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने का समय मांगा है। हम देखेंगे कि उस बैठक से क्या निकलता है, अन्यथा उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) के बयान को ध्यान में रखते हुए मनसे कार्यकर्ता हर टोल बूथ पर इकट्ठा होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चार, तीन और दोपहिया वाहनों से टोल न वसूला जाए। अगर हमें रोका गया तो हम इन्हें आग लगा देंगे।' ठाकरे रविवार को फडणवीस के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटे वाहनों को टोल देने से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सभी राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी महाराष्ट्र को टोल मुक्त बनाने के अपने आश्वासन को लागू नहीं किया।

उन्होंने कहा, उन्हें हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने टोल बूथ पर एकत्र किए गए पैसे से कुछ हिस्सा मिलता है। इसलिए, टोल बूथ कभी बंद नहीं होंगे और आपको कभी अच्छी सड़कें भी नहीं मिलेंगी। राज ठाकरे ने टोल बूथों पर एकत्र किए गए धन की आवाजाही के बारे में सवाल उठाए और पूछा कि एक ही कंपनी को टोल संग्रह के लिए अनुबंध क्यों मिलते रहते हैं। ठाकरे की टिप्पणियों के जवाब में फडणवीस ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि 31 मई 2015 को प्रकाशित एक आदेश के जरिए राज्य में 12 टोल बूथ बंद कर दिए गए थे। बयान में कहा गया, '31 मई 2015 की आधी रात से लागू एक आदेश के जरिए 12 टोल बूथों को बंद कर दिया गया था।

शाहरुख खान को 'पठान' के दौरान मिली थी धमकी, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई किंग खान की सुरक्षा

मुंबईः शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के बाद उनकी एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 'पठान' के बाद 'जवान' भी रोज नया इतिहास रच रहा है। एक महीने में 'जवान' ने वर्ल्डवाइड 1103.27 करोड़ कमा डाले हैं। इसी बीच शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शाहरुख खान को फिल्म 'पठान' के दौरान धमकी मिली थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड के किंग खान की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है।

एक्टर शाहरुख खान को फिल्म 'पठान' के दौरान मिली धमकियों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने किंग खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया की शाहरुख खान को सरकार ने + सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की है। आपको बता दें कि शाहरुख खान को इसके पहले दो पुलिस कांस्टेबल की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा उनके साथ उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहते थे।

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर बोले आदित्य ठाकरे, 'संविधान बदलने वालों को वोट नहीं देगा भारत'

मुंबईः शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को विश्वास जताया कि पांच राज्यों, जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लोग 'इंडिया' गठबंधन द्वारा सुनिश्चित शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मतदान करेंगे. इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में अलग-अलग दिनों में चुनाव होंगे. चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि 7-30 नवंबर तक और 3 दिसंबर को पांच राज्यों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मंच तैयार हो जाएगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लगभग 16 करोड़ मतदाता इन चुनावों में वोट डालने के पात्र होंगे. गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट का शासन है.

आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, लोग भारत गठबंधन द्वारा सुनिश्चित शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मतदान करेंगे. इंडिया यानी भारत उन लोगों को वोट नहीं देगा जो दरार पैदा करते हैं और संविधान को बदलने और हमारे लोकतंत्र और देश को नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं. एउकके प्रवक्ता को टैग करते हुए उन्होंने पूछा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. पुणे और चंद्रपुर की लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है? सीटें अब 6 महीने से अधिक समय से खाली हैं, और पुणे और चंद्रपुर का 6 महीने से लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है.

'राहुल योग्य नेता, लेकिन अच्छा वक्ता नहीं'

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चौंकाने वाला बयान

मुंबईः पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, महाराष्ट्र में कांग्रेस के विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान ने कांग्रेसियों को अचरज में डाल दिया। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ गवर्नेंस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को राजनीति में एक अच्छा वक्ता होने का महत्व समझाते हुए वडेट्टीवार ने अपने ही पार्टी के नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक योग्य नेता हैं, लेकिन वह एक अच्छे वक्ता नहीं हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में आपका एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है।

वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को राजनीति में युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए। लोग 70, 80 और 90 साल की उम्र तक राजनीति में रहते हैं। लेकिन नई पीढ़ी को आने देना चाहिए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। वहीं वडेट्टीवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजनीति की खासियत यह है कि हर राजनेता को लगता है कि वह युवा हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने वडेट्टीवार ने कहा, जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, तो मुझे (चुनाव लड़ने के लिए) 78,000 रुपये मिले। लेकिन यह मत पूछिए कि कितने फंड की जरूरत है, नहीं तो चुनाव आयोग मेरे पीछे पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने वाले अच्छे लोगों को अवसर मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र में जल्दी ही लौट जाएगा मानसून, ठंड दे सकती है दस्तक

महाराष्ट्रः देश के उत्तरी राज्यों में मौसम का हाल तेजी से बदल रहा है। मानसून अब जाने की तैयारी में दिख रहा है। कुछ यही हालात अब महाराष्ट्र में भी नजर आ रहें है। अनुमान लगाया जा रहा है कि, आनेवाले दिनों में राज्य से पूरी तरह मानसून जा चूका होगा। इस दौरान देश के अन्य भागों में जहां जम के बारिश आने की आशंका जताई जा रही है वहीं, राज्य में मौसम शुष्क बना रह सकता है। अंदाज लगाया जा रहा है कि,समुद्र तट के पास बसे जिलों में हवा में नमी बरकार रहने की संभावना है।

पिछले कुछ दिनों से विदर्भ के नाशिक , पुणे और मुंबई में तापमान में वृद्धि हुई है। दिन के समय धुप में तीव्रता बढ़ी होने से आनेवाले दिनों में तापमान के आकड़ो में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। बढ़ते तापमान से लोगों को स्वास्थ्य संबधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। हालांकि, राज्य में सवेरे तापमान में गिरावट से ठंड रह सकती है। इस लिए राज्य से लोगों से निवेदन है कि वे इन हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

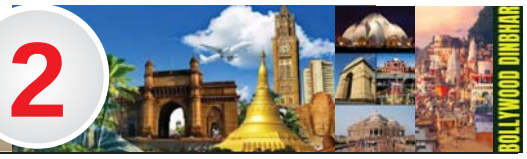

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मुद्रास्फीति के जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति इस समय नीति की समीक्षा कर रही है और शुक्रवार को अपने निर्णय की घोषणा करेगी। संभव है कि उसे पता चला होगा कि मुद्रास्फीति के कुछ कारकों में परिवर्तन आ रहा है। सब्जियों की कीमतें, खासकर टमाटर की कीमतों में गिरावट आई है जबकि अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में पिछली नीतिगत बैठक के बाद से अब तक काफी तेजी देखने को मिली है और अनुमान है कि आने वाले समय में भी वे ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा शायद मुद्रास्फीति की दर में तत्काल इजाफे की वजह न बने क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हो रहे बदलाव के मुताबिक समायोजन करना बंद कर दिया है लेकिन कुछ असर तो फिर भी महसूस होगा। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में रविवार को इजाफा किया गया।

हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त में कुछ कम होकर 6.83 फीसदी रही जबकि जुलाई में यह 7.44 फीसदी के साथ 15 महीने के उच्चतम स्तर पर थी। इस कमी के बावजूद यह दर रिजर्व बैंक द्वारा तय दायरे की ऊपरी सीमा से काफी अधिक है। अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि मौद्रिक नीति समिति नीतिगत रीपो दर में कोई बदलाव नहीं करेगी। मौजूदा चक्र में इस नीतिगत दर में अब तक 2.5 फीसदी का इजाफा किया गया है और वह अभी व्यवस्था में अपना काम कर रही है और निकट भविष्य में मुद्रास्फीति की दर में उल्लेखनीय कमी आती नहीं दिखती। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति अब तक सामान्यीकृत नहीं हुई है और जोखिम बरकरार है। अगस्त माह में खाद्य मुद्रास्फीति दो अंकों के करीब थी और मॉनसून के कमजोर होने के कारण जोखिम बढ़ गया है। कमजोर मॉनसून न केवल खरीफ के फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकता है बल्कि रबी की फसल को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि देश के कई इलाकों में पानी की कमी हो जाएगी। हालांकि कोर मुद्रास्फीति में कमी आई है लेकिन हेडलाइन दरों के कारण नीतिगत चयन मुश्किल हो सकता है।

मुद्रास्फीति संबंधी परिदृश्य और पूर्वानुमान को मद्देनजर रखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि मौद्रिक नीति समिति चालू वित्त वर्ष के लिए 5.4 फीसदी के अपने मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान को संशोधित करती है या नहीं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को 5.2 फीसदी से बढ़ाकर 5.9 फीसदी कर दिया। यह दर रिजर्व बैंक द्वारा तय दायरे की ऊपरी सीमा के निकट है। चार फीसदी के घोषित लक्ष्य से तो यह बहुत अधिक है। मौद्रिक नीति समिति ने अब तक खाद्य मुद्रास्फीति पर आधारित हेडलाइन दरों में इजाफे को देखने का निर्णय लिया है। बहरहाल, मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान में संशोधन के बाद इजाफा होने की स्थिति में समिति को इस सप्ताह नहीं तो आने वाली बैठकों में जरूर नीतिगत कदम उठाने होंगे। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो सब्जियों की कीमतों के कारण बने दबाव की अनदेखी करनी चाहिए क्योंकि यह दबाव कम समय में ही कम हो जाता है। बहरहाल, आपूर्ति क्षेत्र के जोखिम को देखते हुए अनाज और अन्य उत्पादों का दबाव सामान्य होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में वित्त वर्ष का बाकी समय दरें तय करने वाली समिति के लिए काफी जटिल हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी मददगार नहीं है। अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल इस प्रत्याशा में बढ़ रहे हैं कि फेडरल रिजर्व दरों में कम से कम एक और इजाफा कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि 10 वर्ष के भारतीय और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में अंतर 17 वर्ष के निचले स्तर पर है जो डॉलर में मजबूती के साथ पूंजी प्रवाह पर दबाव बनाएगा। चूंकि अमेरिका में ब्याज दरें और लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं इसलिए रुपये पर दबाव बन सकता है जो मुद्रास्फीति संबंधी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

‘न्याय के हित में मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर रोक लगाई गई...’

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव पर ‘‘न्याय के हित में’’ रोक लगा दी गई है। सितंबर में सीनेट चुनाव को निलंबित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली वकील सागर देवरे की याचिका के जवाब में सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह ‘‘राजनीतिक दबाव’’ के कारण किया गया था। देवरे ने 10 सितंबर को होने वाले चुनावों को स्थगित करने के लिए 17 अगस्त को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र को रद्द करने की मांग की थी।

विभाग के उप सचिव अजीत बाविस्कर के हलफनामे में कहा गया है कि परिपत्र के अनुसार, ‘‘चुनाव प्रक्रिया 30 सितंबर, 2023 तक पूरी होनी थी।’’ इसलिए, उसने कहा कि याचिका खारिज किये जाने योग्य है। मतदाता सूची में ‘‘विभिन्न विसंगतियों’’ की ओर इशारा करने वाले भाजपा विधायक आशीष शेलार के एक पत्र के बाद सीनेट चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ‘‘मामले की गंभीरता’’ को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विश्वविद्यालय को ‘‘जांच करने और आवश्यक कदम उठाने’’ का निर्देश दिया। इसलिए जांच करने और तुरंत रिपोर्ट सौंपने के लिए तत्काल कदम उठाए गए।

चूंकि ‘‘एक दिन के भीतर दस्तावेजों को सत्यापित करना अव्यावहारिक है’’ और विस्तृत जांच करने के लिए समय की आवश्यकता थी, विश्वविद्यालय ने सरकार से ‘‘मार्गदर्शन मांगा’’ कि चुनाव प्रक्रिया जारी रखी जाए या नहीं। ‘‘मैं कहता हूं कि उपरोक्त के आलोक में मामले की गंभीरता को देखते हुए और चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए, हमारे कार्यालय ने प्रतिवादी नंबर 3 (विश्वविद्यालय) को सूचित किया कि सभी मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करना और संशोधित मतदाता सूची तैयार करना आवश्यक है। सीनेट चुनाव आयोजित करने से पहले, ‘‘हलफनामे में कहा गया है। इसलिए विश्वविद्यालय को मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन होने तक चुनाव स्थगित करने के लिए कहा गया था।

विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने का अधिकारः महाराष्ट्र सरकार

सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, 2016 की धारा 8(7) के तहत उसे यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी करने का अधिकार है. इसलिए, सरकार ने ‘‘चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के हित में’’ विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए। ‘‘मतदाताओं का सत्यापन आवश्यक है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह, यदि सीनेट चुनाव मतदाताओं के दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना आयोजित किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही की बहुलता होगी और सीनेट चुनाव का उद्देश्य विफल हो जाएगा, ’’हलफनामे में कहा गया है। याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

IT विभाग ने विधायक अबू आसिम आजमी की 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की....

मुंबई : आयकर विभाग (आईटी) ने शनिवार देर रात समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आसिम आजमी की 150 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की। पिछले हफ्ते की शुरूआत में, कर अधिकारियों ने विधायक से जुड़े मुंबई, नवी मुंबई, वाराणसी, कानपुर और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आजमी मुंबई के मानखुर्द में शिवाजी नगर विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं।

आयकर विभाग की लखनऊ स्थित बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने अबू आजमी की अघोषित आय और संपत्तियों की जांच के तहत उनसे जुड़ी संपत्तियों पर कई छापे और तलाशी शुरू की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में वाराणसी में एक वाणिज्यिक टावर में पांच मंजिल, एक आवासीय टावर में 45 फ्लैट और आय के बेनामी संपत्ति कानून के तहत अबू आजमी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी विनायक निर्माण लिमिटेड के बैंक खातों में 10 करोड़ रुपये शामिल हैं। कर विभाग।

तीन दिवसीय आयकर छापेमारी और तलाशी शनिवार की रात को समाप्त हुई, जिसमें कर अधिकारियों ने विनायक समूह की 10 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि, एक रियल एस्टेट संपत्ति के टॉवर उ, वाराणसी के मलदहिया में विनायक प्लाजा को कुर्क कर लिया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये था। 40- 50 करोड़ रुपये और गंगा नदी के किनारे स्थित हमरौतिया इलाके में वरुणा गार्डन परियोजना में 45 फ्लैट बनाए गए। हमरौतिया परियोजना में 2- और 3-बीएचके फ्लैट कथित तौर पर अबू आजमी के स्वामित्व में हैं और उनका बाजार मूल्य लगभग 30-32 करोड़ रुपये है। संपत्तियों को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया था। यह पहली बार है कि कर विभाग ने तलाशी के दौरान बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत चल और अचल संपत्तियों के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं।

पश्चिम रेलवे के यात्री ध्यान दें! अंधेरी स्टेशन पर पुराना फुट ओवर ब्रिज 30 दिनों से अधिक समय तक बंद रहेगा

मुंबई: पश्चिम रेलवे के रखरखाव कार्यों के एक भाग के रूप में, प्लेटफार्म नंबर 4/5 और 6/7 के बीच अंधेरी साउथ (पुराना) फुट ओवर ब्रिज भी 7 अक्टूबर, 2023 से 35 दिनों की अवधि के लिए बंद रहेगा।, प्लेटफार्म नंबर 4/5 पर सीढ़ियाँ और लिफ्ट यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगी।

एक करोड़ 80 लाख का अवैध केमिकल का जखीरा बरामद , मामला दर्ज

1. बगैर परमिशन अवैध तरीके से संचित 207 व 967 प्लास्टिक ड्रामों में रखा था केमिकल...
2. टैंकर द्वारा किया जा रहा था 25 टाइप का ज्वलनशील केमिकल खाली, माफियाओं में हड़कंप

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी के गोदाम बाहुल्य क्षेत्र में अबैध रूप से केमिकल का संचालन करने वाले गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी बदस्तूर जारी है।स्थानीय पूर्णा इलाके के इताडकर वाड़ी के एक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित एक वेयरहाउस में छापा मारकर पुलिस ने 1 करोड़ 80 का अबैध ज्वलनशील केमिकल जप्त किया है।जो कि बिना परमिशन लोहे व प्लास्टिक ड्रम में भंडारण किया गया था।इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर केस तो दर्ज किया है।जिन्हे पुलिस ने सीआरपीसी का नोटिस देकर छोड़ दिया।इस कार्रवाई के बाद केमिकल माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

भिवंडी के गोदाम बाहुल्य इलाके के केमिकल गोदामों पर पुलिस की छापामारी लगातार जारी है।इसी कड़ी में नारपोली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में एपी आई विट्ठल बढ़े के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 6 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे पूर्णा गांव के श्री कॉम्प्लेक्स में स्थित जय अंबे वेयर हाउस के तीन गोदाम में छापामार कर 1 करोड़, 80 लाख 27 हजार516 रुपए कीमत का अति ज्वलंतशील राशयनिक केमिकल का जखीरा बरामद किया है।पुलिस के छापेमारी के दौरान जीजे 12 सिटी 9253 नंबर के टैंकर से प्लास्टिक व लोहे के ड्रमों में केमिकल खाली किया जा रहा था।इस दौरान पुलिस ने 207 लोहे का ड्रम व 967 प्लास्टिक ड्रम में रखा केमिकल जप्त किया है।लेकिन

इन गोदामों में रसायनिक पदार्थों की सुरक्षा हेतु कोई उपाय योजना नहीं था और ना ही इसका भंडारण करने के लिए गोदाम मालिक ने प्रशासन द्वारा किसी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। इसके कारण बड़ा हादसा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।इस मामले में पुलिस संदीप जाधव की शिकायत पर नारपोली पुलिस ने देवेंद्र पाल,राजा पाटील व टैंकर चालक कुमरान कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पेट्रो केमिकल एक्ट और खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण और आयात रूल्स की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नही किया है।मामले की जांच कर रहे एपीआई विट्ठल बढ़े ने बताया कि जप्त किए गए जखीरे में 25 टाइप का अलग अलग केमिकल का समावेश है।जिसे गुजरात से लाया जाता था।

केमिकल गोदामों के कारण खतरे में हजारों लोगों का जीवन

भिवंडी के गोदाम बाहुल्य पूर्णा, काल्हेर, दापोड़ा, कशेली, राहनाल, अंजुरफाटा, मानकोली और वलगांव आदि गोदाम क्षेत्रों में 25 हजार से भी अधिक गोदाम हैं। जिसमें बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी तरीके से अतिज्वलनशील और खतरनाक रसायनों का भंडारण किया जाता है। इन गोदामों में आग से सुरक्षा के कोई उपकरण और उपाय आदि भी नहीं होते हैं। इस तरह सैकड़ों केमिकल गोदामों में आग लगने की वारदातें हमेशा होती रहती हैं। जिसमें जान माल का बड़े पैमाने पर नुकसान भी होता रहता है। यहां तक कि कई बार मजदूरों की जान भी चली जाती है। गोदाम क्षेत्र के इलाके के निवासियों द्वारा इस आशय की बार-बार शिकायत के बावजूद जानलेवा रासायनिक गोदामों को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता है।जिससे अति ज्वलनशील रासायनिक गोदामों के आसपास रहने वाले हजारों लोगों की जान पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है।

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को वरिष्ठ नागरिकों को 8.5 लाख का रिफंड देने का आदेश दिया

मुंबई : एक जिला उपभोक्ता आयोग ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक वरिष्ठ नागरिक को 8.5 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है, जिसे फर्म के एजेंट ने गुमराह किया था। एजेंट ने बेहतर रिटर्न और तीन साल बाद वरिष्ठ नागरिक की बेटी की शादी के लिए पैसे निकालने की क्षमता का वादा किया था। हालाँकि, फर्म ने दावा किया कि पॉलिसियाँ 99 वर्षों के लिए थीं, और जब वरिष्ठ नागरिक ने पॉलिसियाँ वापस लेना और रद्द करना चाहा, तो पुनर्विचार अवधि समाप्त हो गई थी। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना और अप्रैल 2009 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ रिफंड का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी लागत के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। 30 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता पर प्रदान की गई राशि पर ब्याज लगेगा।

4 अक्टूबर को जारी किया गया आदेश, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ चेंबूर निवासी गणपत निवातकर की शिकायत के जवाब में था। वरिष्ठ नागरिक निवातकर ने अपनी बचत के 9 लाख रुपये डाकघर में निवेश किए थे और उन्हें हर महीने प्रत्येक एक लाख रुपये पर 667 रुपये मिलते थे। बजाज के एक एजेंट ने उन्हें 7,000 रुपये के मासिक ब्याज और तीन साल

बाद अपनी बेटी की शादी के लिए धन निकालने की क्षमता का वादा करते हुए कंपनी में निवेश करने के लिए राजी किया।

निवातकर ने बजाज के साथ तीन पॉलिसियां लीं, लेकिन उन्हें केवल 8.15 लाख रुपये की रसीद मिली, और शेष राशि देर से वापस की गई। जब उन्होंने धनराशि निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें बताया गया कि पॉलिसी की अवधि 99 वर्ष है। निवातकर ने बाद में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, और जब बजाज नोटिस के जवाब में उपस्थित नहीं हुए, तो आयोग ने कंपनी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया।

आयोग की सुनवाई ने निर्धारित किया कि निवातकर को पॉलिसी के संबंध में गुमराह किया गया था, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक आमतौर पर 99-वर्षीय पॉलिसी का विकल्प नहीं चुनते हैं। इसमें पाया गया कि नीति में स्पष्टता का अभाव था, और निवातकर को अपेक्षित रिटर्न या अपनी बेटी की शादी के लिए धन निकालने की क्षमता नहीं मिली, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवा की कमियों का कारण बनी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी ने एक गतिरोध पैदा किया था, जिसके कारण ब्याज सहित रिफंड और मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के मुआवजे का आदेश दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में साइबर सुरक्षा परियोजना के लिए 837 करोड़ की मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ उपाय करने के लिए एक साइबर सुरक्षा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उक्त परियोजना के लिए 837 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. साइबर अपराध दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध बनकर उभरा है। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत तकनीक, कुशल जनशक्ति और संसाधनों के साथ उपाय डिजाइन करना आवश्यक हो गया है।

साइबर सुरक्षा परियोजना

साइबर अपराधों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार ने 'साइबर सुरक्षा परियोजना' लागू करने का निर्णय लिया है और इस

संबंध में प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। परियोजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार स्थापित गृह विभाग की उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जायेगा। यह परियोजना विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। कार्यान्वयन छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। समय-समय पर प्रोजेक्ट की समीक्षा की जायेगी. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, कुल पांच वर्षों के लिए 837.86 करोड़ रुपये और करों की राशि खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

परियोजना विवरण

महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। कमांड और नियंत्रण केंद्रः नागरिक एक पोर्टल, मोबाइल ऐप और 24/7 कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के वर्कफ़्लो प्रबंधन मॉड्यूल का उपयोग करके शिकायतों का समाधान किया जाएगा। प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांचः फोरेंसिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से जांच की जाएगी। अधिकारी तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे और जांच में सहायता करेंगे ताकि अपराध की जड़ तक पहुंचना और उसे हल करना संभव हो सके।

गोपीचंद पडलकर ने भाजपा के खिलाफ टिप्पणी के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान की खिंचाई की

बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पडलकर ने बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान की खिंचाई की. रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आरोप लगाया कि भाजपा मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को निशाना बना रही है और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने से रोक रही है। पडलकर ने कहा कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उनके पास भारत के अन्य नागरिकों की तरह सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेज हैं.

पडलकर ने रहमान को झूठा बताते हुए कहा, ''अब्दुल रहमान मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं. दरअसल, मैं सवाल करता हूं कि रहमान आधार और वोटिंग कार्ड बनाने की अपील किसे कर रहे हैं?'' पडलकर ने रहमान की मंशा पर भी सवाल उठाए. पडलकर की यह टिप्पणी रहमान की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा मुसलमानों को मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड बनाने से रोक रही है। रहमान ने यहां तक कहा कि मुसलमान पहला निशाना हैं लेकिन आखिरी नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के बाद, भाजपा का लक्ष्य दलित, ओबीसी, गरीब होंगे और अंत में, पार्टी सभी नागरिकता अधिकारों को छीनने के लिए देश में 'मनुस्मृति' लागू करेगी। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी द्वारा सीएए लाए जाने के बाद रहमान ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

मुंबई हवाई अड्डा 'डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट' चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा

मुंबईः यात्री सुरक्षा और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) ने फंसे हुए विमानों की मदद के लिए एशिया का पहला 'डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट' (डीएआरके) चालू किया है। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। सोमवार। ऊअफ्ड सुविधा में बेहतर स्थायित्व वाले उच्च दबाव उठाने वाले बैग शामिल थे, लेकिन इसके लिए न्यूनतम जनशक्ति की आवश्यकता होती थी और पारंपरिक कम दबाव वाले समकक्षों की तुलना में अधिक कुशल विमान पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया प्रदान की जाती थी।

390 टन के अधिकतम वजन के साथ, DARK बड़े वाणिज्यिक और परिवहन विमानों को तुरंत पुनर्प्राप्त कर सकता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान, बोइंग 777-300एफऔर अन्य शामिल हैं जो रनवे भ्रमण या अन्य घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि रनवे भ्रमण एक ऐसा परिदृश्य है जब विमान टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान रनवे से भटक जाता है या रनवे से आगे निकल जाता है, जो विमानन में एक बड़ी चिंता का विषय है और यात्रियों, विमान और हवाई अड्डे के संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित लेकिन सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में जमीनी तैयारी से लेकर विमान उठाने, डी-बोगिंग और टोइंग तक चरणों का एक सावधानीपूर्वक अनुक्रम शामिल है, और ऊअफ्ड का कॉम्पैक्ट डिजाइन इसकी परिवहन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बचाव दल तेजी से दुर्घटना स्थलों तक पहुंच सकते हैं, ताकि संचालन में व्यवधान कम से कम हो। सीएसएमआईए के पास एकल क्रॉस-ओवर रनवे ऑपरेशन है। अधिकारियों ने बताया कि परिष्कृत किट को तुलनात्मक रूप से कम प्रशिक्षित कर्मियों के साथ संचालित किया जा सकता है, बैग छोटे पदचिह्न पर कब्जा करते हैं, और कम दबाव वाले बैग प्रणाली की तुलना में रिकवरी ऑपरेशन चार गुना तेज होता है। CSMIA की अपनी विमान बचाव और अग्निशमन टीम ने ऊअफ्ड, कानूनी पहलुओं, टेदरिंग, ग्राउंड स्थिरीकरण, कम दबाव वाले बैग का उपयोग करके उठाने की तकनीक, मल्टी-स्लिंग उपयोग और डी-बोगिंग प्रक्रियाओं आदि को संचालित करने के लिए एक गहन पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना शुरू किया। सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए, पूरे ऊअफ्ड को उरटकअ में एक विशाल हैंगर में फैलाया गया था और अलग-अलग इकाइयों को अलग किया गया था, जिसमें 46 कंटेनर, बैग को फुलाने के लिए सिस्टम को पावर देने के लिए एक कंप्रेसर, छह मीटर लंबे फुलाए हुए बैग को स्थिर करने के लिए टेदर शामिल थे।, एक ट्रेलर और विंग संक्रमण, अधिकारियों ने कहा।

इजराइल में फसे 18 हजार भारतीय, रॉकेट हमले में महिला जख्मी

यरूशलम : फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से दागे गए रॉकेट में इजराइली शहर अश्कलोन में नर्स के तौर पर काम करने वाली एक भारतीय महिला जख्मी हो गई है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि महिला की पहचान केरल की शीजा आनंद के तौर पर हुई है और शनिवार को हुए हमले में उनका हाथ और पैर जख्मी हो गया था तथा उनका नजदीकी अस्पताल में तत्काल इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि महिला को बाद में दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी हालत स्थिर है। भारतीय मिशन ने मदद के लिए उनसे संपर्क किया है और वह केरल के कन्नूर जिले में रहने वाले उनके परिवार के संपर्क में है। दूतावास के एक सूत्र ने बताया, ''उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है और हम शीजा और उनके परिवार के लगातार संपर्क में हैं। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास ने शनिवार सुबह अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल में सैनिकों समेत कम से कम 700 लोगों की मौत हो गई है और 2100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह कम से कम 50 साल में इजराइल के लिए सबसे घातक दिन है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, इजराइल के जवाबी हमलों में गाजा पट्टी में करीब 500 लोगों की मौत हुई है और दो हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

राजस्थान में बज गई चुनावी रणभेरी, इस तारीख को होगा मतदान, इन दिन आएंगे नतीजे

राजस्थान : राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा. सोमवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है. तो आइए जानते हैं कि राजस्थान में कब और कितने चरण में वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग के मुताबिक, राजस्थान में 23 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा. नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राजस्थान में चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी. जबकि 6 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है. नामांकन की जांच सात नवंबर को की जाएगी. नौ नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा. इसमें 23 तारीख तक बदलाव किया जाएगा. आयुक्त ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को कम से कम तीन बार न्यूजपेपर में अपने बारे में जानकारी देनी होगी. साथ ही उनकी पार्टी को भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया. बता दें कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं. वहीं, विपक्षी दल भाजपा भी सत्ता में वापसी करने के लिए जमकर पसीना बहा रहा है. बीजेपी यहां पर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है. वहीं, कांग्रेस अशोक गहलोत को सामने रखकर चुनाव मैदान में है.

राजस्थान में इस बार इतने हैं मतदान

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान समेत पांचों राज्यों में चुनाव आयोग की टीम ने दौरा कर जानकारी प्राप्त की है. यहां की राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई हैं. 51 हजार 756 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. पिछली बार इनकी संख्या 51 हजार 796 थी. राजस्थान में इस बार मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 है, जिसमें से एक लाख 41 हजार 890 सर्विस वोटर्स हैं. राज्य में 18-19 साल के 22 लाख चार हजार 514 वोटर्स हैं. वही, पीडब्ल्यूडी वोटर्स 5 लाख 60 हजार 990 हैं. इसके अलावा थर्ड जेंडर 606 और सीनियर सिटीजन के 11 लाख 78 हजार 285 मतदाता हैं.

भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा स्कूल को बंद करने के फैसले के बाद, भिवंडी मनपा मुख्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी शहर के असबीबी इलाके में स्थित मनपा स्कूल नंबर 65 में स्कूल भवन सुविधाओं की कमी को कारण बताते हुए स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। इसके विरोध में अभिभावक अपने बच्चों के साथ भिवंडी महानगरपालिका मुख्यालय पहुंचे और प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी नियुक्त होने के बाद भी मुख्यालय के अंदर लाबी में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मनपा प्रशासन की नींद टूटी, होश आया और स्कूल को उसी स्थान पर जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। गौरतलब हो कि कल्याण रोड पर स्थित आसबीबी में एक पुराना स्कूल नंबर 65 है और इस स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक कुल 60 छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल में छात्रों को बैठने की कमी , पीने के पानी और शौचालय की सुविधा की कमी के बारे में कई शिकायतों के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक सुमोतो दायर किया। भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा इस पर कुछ नहीं बोलने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद तत्कालीन कमिश्नर ने अस्थाई तौर पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की और स्कूल शुरू हुआ। लेकिन मनपा प्रशासन ने स्कूल को फिर से बंद करने का फैसला सुनाया और छात्रों को पढ़ने के लिए एक किलोमीटर दूर रावजी नगर के स्कूल नंबर 73 में स्थानांतरित कर दिया।

बच्चों के सड़क पार करने से दुर्घटना होने की आशंका के चलते स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने इस फैसले का विरोध जताया और वे मनपा मुख्यालय पर लगी सिक्योरिटी को धता बताते हुए सीधे भिवंडी मनपा मुख्यालय की बिल्डिंग के नीचे की लाबी पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। जिसको देखकर मनपा अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने घबराकर आनन-फानन में स्कूल को उसी स्थान पर जारी रखने का निर्णय लिया। मनपा प्रशासन के इस निर्णय से अवगत होकर छात्रों और अभिभावकों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com ,